अध्याय 16

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां

भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है तथा सम्पूर्ण विश्व इसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति को स्वीकार कर रहा है। लेकिन इस विकास के साथ–साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। समाचारपत्रों, टी.वी. चैनलों, जन सामान्य की चर्चाओं, इंटरनेट आदि से मिलने वाली विभिन्न सूचनाओं पर हम विचार करें तो पाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न अनेक चुनौतियों में मूल्यवृद्धि, गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्याएं सम्भवतः सर्वाधिक गम्भीर हैं। ये समस्याएं कमोबेश एक साथ जुड़ी हुई हैं तथा स्वतंत्रता के बाद से अब तक निरन्तर बनी हुई हैं।

गरीबी तथा बेरोजगारी को भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन समस्याओं के कारण न केवल अर्थव्यवस्था को नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ता है अपितु समाज को भी अनेक हानियां वहन करनी पड़ती हैं। इनके सम्बन्ध में हमारी सामान्य समझ और ज्ञान को व्यापक बनाने की दृष्टि से हमें इनका अर्थ, स्वरूप, कारण, परिणाम तथा रोकने के उपायों की प्रारम्भिक जानकारी होना आवश्यक है।

16.1 मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति (Inflation)

हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा जीवन को आनन्दमय बनाने के लिए बाजार से अनेक प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करते हैं। आपने भी निश्चित ही कपड़े, खिलौने, जूते, चप्पल, मिठाइयां, आइसक्रीम आदि खरीदे होंगे या अपने परिजनों को परिवार की आवश्यकता की वस्तुऐं खरीदते देखा होगा। वस्तुओं के क्रय के दौरान सामान्यतया देखने को मिलता है कि अधिकांश वस्तुओं के लिए हमें पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी होती है। इस बढ़ती कीमतों के परिदृश्य को मूल्य वृद्धि के रूप में जाना जाता है। आर्थिक शब्दावली में मूल्य वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति शब्द का प्रयोग किया जाता है।

कीमत– मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है, वह उस वस्तु अथवा सेवा की कीमत कहलाती है।

पारिभाषिक तौर पर सामान्य कीमत स्तर में सतत् वृद्धि की स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। यह अनेक वस्तुओं अर्थात् वस्तु समूह के लिए कीमत में औसत वृद्धि को बताती है। यह सम्भव है कि बाजार में आप सब्जियों की कीमतों में वृद्धि अनुभव कर रहे हों तथा समाचार पत्र कम होती मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति बता रहे हों। इसके विपरीत यह भी सम्भव है कि आप किसी वस्तु या कुछ वस्तुओं की कीमतों में कमी महसूस कर रहे हों लेकिन समाचार पत्र बढ़ती मुद्रास्फीति बता रहे हो। मुद्रास्फीति का सम्बन्ध अर्थव्यवस्था में अनेक वस्तुओं (वस्तु समूह) की कीमतों के औसत स्तर (सामान्य कीमत स्तर) में वृद्धि से है न कि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि मात्र से।

सामान्य कीमत स्तर का तात्पर्य अनेक वस्तुओं या एक वस्तु समूह की कीमतों के औसत स्तर से है। अतः सामान्य कीमत स्तर किसी एक वस्तु की कीमत को नहीं बताता अपितु यह तो एक निश्चित वस्तु समूह की औसत कीमत को व्यक्त करता है।

16.1.1 मुद्रास्फीति का माप

मुद्रास्फीति की हानियों से बचने के लिए तथा इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु इसे मापा जाना आवश्यक है। अतः सभी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति की दर के मापन हेतु भिन्न–भिन्न प्रकार के कीमत सूचकांक बनाती है। सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए भारत में भी अनेक प्रकार के कीमत सूचकांक तैयार किये जाते हैं। इन सूचकाकों में थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा राष्ट्रीय आय अवस्फीति कारक प्रमुख हैं। ये सूचकांक एक निश्चित वस्तु समूह की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन का माप करते हैं। मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित कीमत सूचकांक में समय के साथ–साथ होने वाले आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन से मापा जाता है।

सूचकांक अलग–अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करते हैं। सूचकांक दिये गये आधार के सापेक्ष किसी चर के आकार में परिवर्तन को दर्शाते हैं।

16.1.2 भारत में मुद्रास्फीति

भारत में मुद्रास्फीति की दर को सामान्यतः थोक मूल्य

सूचकांक से मापा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही उच्च मुद्रास्फीति की दर भारत में एक गम्भीर समस्या रही है यद्यपि 1950 ई. के दशक में मुद्रास्फीति की औसत दर मात्र 1.7 प्रतिशत थी। लेकिन 1960 के दशक में यह 6.4 प्रतिशत हो गयी। सत्तर के दशक में यह 9 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गयी। ऊँची मुद्रास्फीति का यह दौर 1995 ई. तक चलता रहा । इसके पश्चात मुद्रास्फीति में कुछ कमी देखने को मिली। वर्ष 2000–01 से 2011–12 के मध्य यह लगभग 4.7 प्रतिशत बनी रही।

16.1.3 मुद्रास्फीति से हानियाँ

एक सामान्य व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति के कारण उसे पहले की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन वास्तव में समस्या यहीं पर समाप्त नहीं होती। मूल्यवृद्धि व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के लिए हानि की एक श्रृंखला का निर्माण करती है। इससे मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की एक निश्चित मात्रा से पूर्व के वर्षों की तुलना में कम मात्रा में वस्तुयें और सेवायें खरीदी जा सकती हैं। लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य को तेजी से गिराती है।

मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है जो कि मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की क्षमता को बताता है।

मुद्रास्फीति के कारण निश्चित वेतन तथा मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग को भी हानि होती है। इस वर्ग को उनके समान कार्यों एवं सेवाओं के लिए प्राप्त समान राशि की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे बचतकर्ता की बचत का मूल्य गिरता है तथा ऋणी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है क्योंकि उसे कम मूल्यवाली मुद्रा वापस चुकानी होती है।

मुद्रास्फीति का प्रभाव आर्थिक विकास की दर, गरीबी, बेरोजगारी, आय एवं धन के वितरण आदि पर भी पड़ता है जिसका अध्ययन आगे की कक्षाओं में किया जायेगा। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति विकास के लाभों को समाप्त कर देती है अतः इसे नियंत्रण में रखे जाने की आवश्यकता होती है।

16.1.4 मुद्रास्फीति का माँग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्वरूप

मुद्रास्फीति को कौन निर्धारित करता है अर्थात मुद्रास्फीति के क्या कारण है। यह कभी कम तो कभी ज्यादा क्यों होती है ?इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए समग्र माँग तथा समग्र पूर्ति की अवधारणाओं के द्वारा मूल्य वृद्धि के माँग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्वरूप को समझना आवश्यक है। एक देश में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं पर प्रत्याशित व्यय का योग समग्र माँग कहलाता है। समग्र माँग का स्तर उपभोग हेतु माँग, निवेश हेतु वस्तुओं की माँग, सरकार द्वारा वस्तुओं के क्रय तथा विदेश क्षेत्र को विशुद्ध निर्यात का योग होता है। समग्र पूर्ति का तात्पर्य उत्पादन की उस मात्रा से है जिसे अर्थव्यवस्था दिये गये संसाधनों तथा उपलब्ध तकनीक से उत्पादित कर सकती है।

अर्थव्यवस्था में समग्र माँग तथा समग्र पूर्ति के बीच उत्पन्न होने वाले असंतुलन कीमतों में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जब समग्र माँग में वृद्धि होती है या समग्र पूर्ति में कमी आती है या दोनों स्थितियाँ एक साथ उत्पन्न हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बनता है। समग्र माँग में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इसे माँग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। लागतों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं।

16.1.5 मुद्रास्फीति के कारण

मुद्रास्फीति का कोई एक सुस्पष्ट तथा निश्चित कारण नहीं है। यह अनेक कारणों का संयुक्त परिणाम होती है। मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारक अग्रांकित हैं–

(क) मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि–

विश्व के अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मुद्रा की पूर्ति का आवश्यकता से अधिक होना है। अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है तो अत्यधिक मुद्रा अपेक्षाकृत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ती है इससे दिये गये कीमत स्तर पर समग्र माँग का स्तर समग्र पूर्ति से अधिक हो जाता है और कीमतों में वृद्धि की प्रवृति उत्पन्न हो जाती है।

(ख) औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि–

स्वतंत्रता के पश्चात अधिकांश वर्षों में भारत में औद्योगिक विकास की दर अपेक्षित दर से कम रही। 1965 से 1985 के मध्य तो उद्योगों का निष्पादन बहुत निराशाजनक रहा। अनेक कारणों से औद्योगिक उत्पादों की माँग में लगातार वृद्धि होती रही, लेकिन उद्योग इस माँग को संतुष्ट करने में असफल रहे। औद्योगिक क्षेत्र में माँग के आधिक्य ने कीमतों को तेजी से बढ़ाया।

अनेक सुधारों और क्रांतियों के बावजूद भारतीय कृषि की उत्पादकता बहुत नीची है। इसके साथ भारतीय कृषिगत

उत्पादन माँग को संतुष्ट करने में असफल रहा। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादों की उच्च माँग इनकी कीमतों को लगातार तेजी से बढ़ा रही है।

(ग) सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर–

विकास के साथ–साथ बढ़ते दायित्वों के कारण सरकारी व्ययों में लगातार वृद्धि हुई है। सरकारी व्यय की यह वृद्धि समाज के लिए पूर्णतः लाभदायक नहीं है। सरकार द्वारा किया जाने वाला अनुत्पादक व्यय समग्र पूर्ति को नहीं बढ़ाता, लेकिन जनता को क्रय शक्ति प्रदान करके समग्र माँग को बढ़ा देता है। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(घ) अन्य कारण–

बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए माँग का स्तर सदैव उच्च बना रहता है, जो कीमतों को तेजी से बढ़ाता है। अनेक वस्तुओं का मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। जब सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए इन वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाती है, तो अर्थव्यवस्था में मूल्यवृद्धि की समस्या देखने को मिलती है। महंगे आयात, कृषिगत उत्पादों की ऊँची न्यूनतम समर्थन कीमत तय करना, आय का बढ़ता स्तर, अप्रत्यक्ष करों का ऊँचा स्तर, मजदूरी दरों में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में बाधायें इत्यादि कारणों से भी मुद्रास्फीति बढ़ती हैं।

16.1.6 मुद्रास्फीति के नियन्त्रण के उपाय

मुद्रास्फीति का कोई एक कारण नहीं है इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना भी सरल नहीं है। मुद्रास्फीति देश के सामने अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न करती हैं। अतः इसे रोका जाना आवश्यक होता है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु किए जा सकने वाले उपाय निम्नलिखित हैं –

(क) मौद्रिक उपाय–

मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु केन्द्रीय बैंक (भारत का केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है।) द्वारा मौद्रिक उपाय अपनाये जाते हैं। इन उपायों के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा, साख की उपलब्धता तथा ब्याज दरों को प्रभावित करके समग्र माँग को कम करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। जब मुद्रा की मात्रा या साख की उपलब्धता में कमी आती है तो समग्र माँग भी कम हो जाती है जिससे मुद्रास्फीति भी कम हो जाती है।

(ख) राजकोषीय उपाय–

सरकार द्वारा राजकोषीय उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में सरकार करारोपण, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋणों में परिवर्तन करके समग्र माँग को नियंत्रित करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। सरकार प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर तथा सार्वजनिक व्यय में कमी करके तथा सार्वजनिक ऋण लेकर समग्र माँग को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को कम कर सकती है। सरकार अप्रत्यक्ष करों को कम करके एवं उत्पादक निवेश बढ़ाकर समग्र पूर्ति में वृद्धि के माध्यम से भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है।

(ग) अन्य उपाय–

उपर्युक्त वर्णित उपायों के अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य की दूकानों पर उपलब्ध करवा कर, आधिक्य माँग वाली वस्तुओं का आयात करके, प्रशासनिक कीमतों में कमी करके भी मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। सरकार द्वारा कृषि एवं उद्योगों को दिया जाने वाला निवेश प्रोत्साहन भी समग्र पूर्ति को बढ़ाकर मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण में उपयोगी होता है।

16.2 गरीबी

गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन–निर्वाह न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असफल हो जाता है। गरीबी एक व्यापक अवधारणा है, जिसके अनेक आयाम हैं लेकिन सामान्य तौर पर गरीबी शब्द का तात्पर्य आर्थिक अपवेचन से लिया जाता है अर्थात् धन तथा सम्पदा के अभाव को गरीबी कहा जाता है।

हम देखते हैं कि एक ओर कुछ लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो बहुत बड़े और सुन्दर हैं एवं दूसरी ओर कुछ लोगों के पास घर ही नहीं होते हैं या कच्चे घर होते हैं। आपने अनेक ऐसे बच्चों को देखा होगा जो विद्यालय आने में समर्थ नहीं हैं। उन्हें अपनी तथा परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम पर जाना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि समाज में कुछ लोग अमीर होते हैं तथा कुछ लोग गरीब होते हैं। गरीबों के पास धन का अभाव होता है तथा वे अपने जीवन के लिए आवश्यक भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का न्यूनतम स्तर भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

16.2.1 निरपेक्ष गरीबी तथा सापेक्ष गरीबी

निरपेक्ष गरीबी–

इसमें जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं का एक मानक स्तर तय कर लिया जाता है। इसके पश्चात् उन लोगों को निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में माना जाता है जो न्यूनतम आवश्यकताओं के मानक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाये। अतः निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। निरपेक्ष गरीबी का विचार अविकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है। भारत जैसे राष्ट्रों में जब गरीबी शब्द का उपयोग किया जाता है, तो इसका तात्पर्य निरपेक्ष गरीबी से ही होता है।

न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं का मानक स्तर सभी राष्ट्रों में अलग अलग होता है। यह मानक स्तर राष्ट्र के विकास की स्थिति, लोगों के जीवन स्तर, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति आदि पर निर्भर करता है। ये कारक सभी राष्ट्रों में अलग–अलग हैं अतः सभी राष्ट्रों में निरपेक्ष गरीबी के निर्धारण हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक स्तर अर्थात् गरीबी रेखा भी भिन्न–भिन्न होती है।

सापेक्ष गरीबी–

समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन या उपभोग व्यय के वितरण में सापेक्षिक असमानताओं का माप, सापेक्षिक गरीबी कहलाती है। यह विचार विकसित राष्ट्रों में अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है।

16.2.2 भारत में गरीबी का माप

भारत में गरीबी के मापन हेतु प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 ई. में किया था। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा भी गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किये गये थे। स्वतंत्रता के पश्चात गरीबी रेखा के निर्धारण तथा गरीबी को परिभाषित करने हेतु 1962 ई. में योजना आयोग द्वारा एक अध्ययन–दल का गठन किया गया। 1971 में वी0 एम0 दांडेकर तथा नीलकंठ रथ ने गरीबी के लिए एक कसौटी को परिभाषित किया। इस संदर्भ में 1979 का वर्ष महत्त्वपूर्ण है, जब ''प्रभावी उपभोग माँग एवं न्यूनतम आवश्यकता पर कार्यदल'' जिसे वाई0 के0 अलघ कमेटी भी कहते हैं के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन अवश्य मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उपभोग में इससे कम कैलोरी प्राप्त करता, तो उसे गरीब माना जाता था। इसे कैलोरी या उपभोग आधारित गरीबी रेखा कहा गया। इसके पश्चात डी. टी. लकड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर तथा सी. रंगराजन की अध्यक्षता में भी योजना आयोग द्वारा गरीबी के अनुमान लगाने हेतु कार्यदलों का गठन किया गया। लकड़ावाला फार्मूले द्वारा 1993–94 तथा 2004–05 के लिए गरीबी के अनुमान लगाये गये थे।

सुरेश तेंदुलकर तथा सी. रंगराजन के द्वारा गरीबी निर्धारण का आधार उपभोग–व्यय माना गया है। इन्होंने गरीबी रेखा के मापन हेतु खाद्यान तथा गैर–खाद्यान वस्तुओं की न्यूनतम मात्राओं का समूह (गरीबी रेखा बास्केट) तैयार किया तथा यह अनुमान लगाया की बाजार कीमतों के आधार पर वस्तुओं की इस न्यूनतम मात्राओं के समूह (गरीबी रेखा बास्केट)को क्रय करने हेतु कितने उपभोग व्यय की आवश्यकता है।

उन्होंने अपने अनुमानों में पाया की वर्ष 2011–12 में शहरी क्षेत्रों में 1000 रु से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रु से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय करने वाला व्यक्ति गरीब है। सुरेश तेंदुलकर के अनुमान के आधार पर भारत में 21.92 प्रतिशत लोग गरीब हैं अर्थात् लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं।

सी. रंगराजन ने वर्ष 2011–12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रु प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रु प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा माना है। इस आधार पर वर्ष 2011–12 में भारत में गरीबी 29.5 प्रतिशत है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ऑक्सफॉर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बनाया। जिसे 2010 के मानव विकास प्रतिवेदन में जारी किया गया। इस निर्धनता सूचकांक के आकलन हेतु तीन आयामों तथा दस सूचकों का प्रयोग किया गया।

भारत में विश्वसनीय समंकों के संकलन का कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा चलाये गये विभिन्न दौरों में एकत्रित किये गये उपभोग व्यय सम्बंधी समंकों के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञ गरीबी का अनुमान लगाते हैं।

रिकॉल अवधि (Recall Period)

गरीबी आकलन एवं अनुमान हेतु किये जाने वाले समंकों के संकलन में दो प्रकार की रिकॉल अवधि का उपयोग किया जाता है। समान रिकॉल अवधि में (Uniform Recall Period-URP) 30 दिन की अवधि के लिए उपभोग व्यय के समंक एकत्र किये जाते हैं। मिश्रित रिकॉल अवधि (Mixed Recall Period-MRP) में खाद्यान्न तथा गैर–खाद्यान्न वस्तुओं पर उपभोग व्यय के समंक एकत्रित करने के लिए दो अलग–अलग संदर्भ अवधियों (30 दिन तथा 365 दिन) का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है।

16.2.3 गरीबी के कारण

भारत में गरीबी के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक कारण उत्तरदायी है। इन कारणों का विवेचन निम्नवत है–

(क) सामाजिक कारण

भारत में सामाजिक ढाँचा गरीबी को बढ़ाने वाला रहा है। जन्म, विवाह एवं मृत्यु से सम्बंधित अनेक परम्पराएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को कर्जदार बना देती हैं। व्यक्ति जीवनपर्यन्त उस कर्ज के बोझ से बाहर नहीं आ पाता है। इसी प्रकार बेटे के जन्म की चाह ने जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया है जो गरीबी का एक

बड़ा कारण है। जातियों में विभाजित ग्रामीण हिन्दू समाज ऐसा था कि जहाँ समाज के एक बड़े पिछड़े हिस्से को लगातार हीन अवस्था में बनाये रखा गया। इस वर्ग को लम्बे समय तक गरीबी से बाहर आने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया।

गरीबी के कारणों की चर्चा में रेग्नार नर्क्से का नाम अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। नर्क्से ने गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना प्रस्तुत की और बताया कि एक राष्ट्र इसलिए गरीब होते है कि वह पहले से ही गरीब है। गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ यह है कि गरीबी का कारण भी गरीबी है तथा गरीबी का परिणाम भी गरीबी ही हैं।

(ख) आर्थिक कारण–

भारत की अधिकांश जनसंख्या आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार रही है। आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति में लोग शिक्षा तथा स्वास्थ्य मे निवेश नहीं कर पाते हैं जिससे उनकी गुणवत्ता निम्न बनी रहती है। निम्न गुणवत्ता के कारण इन्हें कम आय प्राप्त होती है और ये गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाते हैं। स्वतंत्रता के पहले अधिकांश भारतीय कृषि पर निर्भर करते थे तथा इनका संसाधन आधार बहुत कमजोर था । निवेश की कमी के कारण कृषिगत उत्पादकता निम्न बनी रही है। इन्हीं कारणों से लघु कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को प्राप्त होने वाली आय आज भी जीवन–निर्वाह के न्यूनतम स्तर पर बनी हुई हैं। आर्थिक पिछड़ापन व्यक्ति के पास अवसरों की उपलब्धता कम कर देता है। अवसरों के अभाव में व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाता है।

(ग) राजनैतिक कारण–

राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी भी भारत में भीषण गरीबी के लिए उत्तरदायी है। पांचवी पंचवर्षीय योजना से पूर्व सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये। गरीबी निवारण हेतु विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक योजनाएं बनायी गयीं लेकिन प्रबल राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण उन योजनाओं के लाभ लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुँच पाये। हमारे प्रशासनिक तंत्र में भी अनेक रिसाव हैं। वर्तमान सरकार द्वारा अपनायी जा रही प्रत्यक्ष लाभ–हस्तांतरण की नीति के कारण इन रिसावों में भारी कमी आयी है।

(घ) अन्य कारण–

भारत में भयंकर गरीबी के लिए शिक्षा का निम्न स्तर, उद्यमी प्रवृत्तियों का अभाव, रोजगारपरक तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, कमजोर आधारभूत संरचना, पूँजी निर्माण का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता पर उत्तरदायी है। इनसे देश में उत्पादकता तथा आय का स्तर निम्न बना रहता है जो कि गरीबी का बड़ा कारण है। गरीबों में आत्मविश्वास की भी कमी होती है तथा वे आर्थिक जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं होते, अतः स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाते हैं। मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि से भी गरीबी बढती है। कीमतों में वृद्धि के कारण अनेक लोग अपने जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकताओं से सम्बन्धित वस्तुओं को क्रय नहीं कर पाते तथा गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं।

पढ़ें:

राजेश अपनी पत्नी, चार बच्चों और वृद्ध माता–पिता के साथ शहर की कच्ची बस्ती में रहता था। अपने परिवार के पालन–पोषण हेतु वह सुबह जल्दी उठकर समाचार–पत्रों का वितरण करता तथा दिन में एक सेठ के कारखाने में काम करता। वह अशिक्षित था, अतः उसे बहुत कम मजदूरी मिलती थी । इस अल्प मजदूरी का बड़ा हिस्सा माता–पिता के स्वास्थ्य की देखभाल पर खर्च हो जाता। सेठ द्वारा नयी मशीनें खरीदे जाने के कारण अब उसे कम लोगों की जरूरत थी। इसी समय अत्यधिक कार्य करने एवं अच्छा भोजन नहीं मिलने के कारण राजेश का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। सेठ ने उसको नौकरी से निकाल दिया। अशिक्षित होने के कारण उसके पास रोजगार के अन्य अवसरों का अभाव था तथा उसके पास इतनी योग्यता एवं धन भी नहीं था कि वह स्वयं का व्यवसाय कर सके। अब राजेश तथा उसके परिवार के लिए जीवनयापन करना भी दूभर हो गया।

विचार करें

(क) राजेश के परिवार को गरीबी की स्थिति में माना जाये या नहीं।

(ख) क्या बेरोजगारी तथा गरीबी में कोई गहन सम्बंध है ?

(ग) जनसंख्या तथा गरीबी के मध्य क्या सम्बंध है ?

(घ) क्या शिक्षा रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है ?

16.2.4 गरीबी निवारण के उपाय

(क) शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार–

समाज में व्याप्त अधिकांश बुराइयों की जड़ अशिक्षा है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य तथा उपलब्ध अवसरों का लाभ प्राप्त नहीं होता है। गरीबी की समस्या के उन्मूलन हेतु सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार किये जाने की आवश्यकता है। शिक्षा प्राप्ति के फलस्वरूप श्रम की कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार द्वारा भी गरीबों की कुशलता एवं योग्यता को बढाकर उत्पादकता को बढाया जा सकता है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सामान्य श्रम को मानव पूँजी में परिवर्तित कर देते हैं। मानव पूँजी के कारण ही जापान तथा अमेरिका आर्थिक शक्ति बन पाये हैं। अतः सरकार को गरीब वर्गों में शिक्षा का प्रसार

एवं स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार करना चाहिए।

(ख) रोजगार के अवसरों में वृद्धि–

बेरोजगारी तथा गरीबी में गहरा सहसम्बध है। इन दोनों समस्याओं का सहअस्तित्व पाया जाता है अतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके गरीबी की समस्या को समाप्त या कम किया जा सकता है। समाज के जिन व्यक्तियों के पास कौशल या योग्यता है उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करके तथा संसाधन उपलब्ध करवाकर गरीबी के जाल से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे गरीब जिनमें कौशल का अभाव है उन्हें मजदूरी रोजगार प्रदान करके उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि की जा सकती है यद्यपि मजदूरी रोजगार एवं स्वरोजगार के अनेक कार्यक्रम वर्तमान तथा पूर्व सरकारों द्वारा चलाये गये हैं लेकिन यह इतने पर्याप्त नहीं थे कि गरीबी की समस्या का समाधान कर सके। गरीबी निवारण हेतु शिक्षा को अधिक रोजगारपरक बनाकर रोजगार के अवसरों का विस्तार करना आवश्यक है।

(ग) सामाजिक कुप्रथाओं पर नियत्रंण की आवश्यकता–

भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं ने समाज के विभिन्न वर्गों एवं व्यक्तियों के लिए अवसरों को सीमित रखा तथा उन्हें लगातार गरीब बनायें रखा। अनेक सामाजिक प्रथाऐं जैसे शादी या मृत्यु के समय किया जाने वाला भारी व्यय अनुत्पादक व्यय है जिससे गरीब व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है और वह कभी भी गरीबी के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाता । भारतीय व्यक्ति गरीबी को भाग्य की देन मानकर भी प्रयासहीन हो जाता है। समाज तथा संस्कृति में व्याप्त इन कुप्रथाओं को जब तक दूर नहीं किया जाता तब तक गरीबी निवारण सम्भव प्रतीत नहीं होता ।

(घ) जनसंख्या पर नियंत्रण–

भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। स्वतंत्रता के पश्चात् स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार ने मृत्यु दर में तेजी से कमी की लेकिन जन्मदर में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। जन्मदर तथा मृत्युदर के मध्य अन्तर बढ़ने के कारण भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। इस तेज वृद्धि के कारण गरीबों की जो थोड़ी–बहुत सम्पदायें हैं उनका तेजी से विभाजन होता है तथा गरीब व्यक्ति अधिकाधिक गरीब हो जाता है। बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण गरीब परिवार उनके लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य में भी निवेश नहीं कर पाता अतः गरीबी निवारण हेतु जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण लगाया जाना आवश्यक है।

(ड) लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों को पहुँचाना –

गरीबी निवारण हेतु अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये गये लेकिन इन कार्यक्रमों में अनेक रिसाव थे जिससे इनके अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इन रिसावों के कारण गरीबों हेतु आवंटित संसाधनों का एक बडा हिस्सा गैर गरीबों को आवंटित हो जाता है। यदि सरकार गरीबी निवारण हेतु गम्भीर है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुँचे।

16.2.5 गरीबी निवारण हेतु अपनाये गये उपाय

1970 के दशक से पहले सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु सार्थक प्रयास नहीं किये गये। सरकार को यह विश्वास था कि आर्थिक प्रगति के प्रभाव समाज के कमजोर वर्ग तक धीरे–धीरे पहुँच जाएँगे और गरीबी की समस्या का समाधान आर्थिक विकास के साथ स्वतः ही हो जायेगा। बाद में यह स्वीकार किया गया कि भारत की विकास दर बहुत धीमी है तथा इसके लाभ भी अपेक्षित मात्रा में गरीबों तक नहीं पहुँच पाये हैं। 1970 के पश्चात् गरीबी निवारण हेतु भारत में नयी बहुआयामी नीति अपनायी गई। मजदूरी रोजगार एवं स्वरोजगार के अनेक कार्यक्रम चलाए गये तथा रोजगार प्रदान करके गरीबी की समस्या को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान करके उन्हें जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुयें एवं सेवाएं कम कीमत पर या मुफ्त में उपलब्ध करवाने की नीति भी अपनायी। सरकार द्वारा किये गये इन अनेक नीतिगत उपायों से गरीबी में कमी तो आयी लेकिन गरीबी में यह कमी संतोषजनक नहीं है।

16.3 बेरोजगारी

कोई व्यक्ति कार्य के योग्य एवं इच्छुक हो, लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है वह बेरोजगार है। भारत युवाओं का देश है लेकिन यह युवा शक्ति तभी लाभदायक होगी जब इसे उचित रोजगार में नियोजित किया जा सके। अपने गाँव या शहर में बहुत से लोग कृषि कार्य में लगे हैं तो अनेक लोग व्यवसाय में कार्यरत हैं। साथ ही कुछ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाओं में कार्यरत हैं। प्रत्येक रोजगार प्राप्त व्यक्ति काम से स्वयं धन प्राप्त करता है तथा वह अपने राष्ट्र के लिए भी उत्पादन में योगदान करता है। रोजगार से व्यक्ति को धन की प्राप्ति के साथ अनुभव भी प्राप्त होता है जिससे उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसे धन तथा कुशलता की हानि होती है और वह मानसिक अवसाद का सामना भी करता है। बेरोजगारी एक व्यक्ति को अकुशल तथा असामाजिक बना देती है। बेरोजगारी की स्थिति व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक हानियों का निर्माण करती है।

बेरोजगारी को समझने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम

श्रमशक्ति, कार्यशक्ति तथा बेरोजगारी की दर को समझा जाये। श्रमशक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है। इसमें रोजगारशुदा तथा बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं। कार्य शक्ति, श्रम शक्ति का वह भाग है जो रोजगार में है। प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलने पर वह बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी दर, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से अनुपात है।

बेरोजगारी दर के अनुमान तीन अलग–अलग दृष्टिकोण क्रमशः सामान्य स्थिति, साप्ताहिक चालू स्थिति तथा चालू दैनिक स्थिति पर लगाये जाते हैं जिनका अध्ययन हम उच्चतर कक्षाओं में करेंगे।

भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने हेतु भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन **(NSSO)** द्वारा अलग–अलग दौरों का आयोजन करके आँकड़े जुटाये जाते हैं। बेरोजगारी सम्बंधी आंकड़े जुटाने के लिए इस संगठन ने 2011–12 में 68 वाँ दौर चलाया था। इस दौर में पाया गया कि सामान्य स्थिति के आधार पर प्रति हजार जनसंख्या पर श्रम शक्ति 395 तथा कार्यशक्ति 386 रही व 2011–12 के 68वें दौर में सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर 2.3 प्रतिशत है।

16.3.1 बेरोजगारी के प्रकार

(क) मौसमी बेरोजगारी –

बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं जो मौसम बदलने के साथ समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यवसाय वर्ष की एक निश्चित अवधि या मौसम में ही रोजगार देते हैं। कृषि तथा कृषि आधारित उद्योग इसका श्रेष्ठ उदाहरण हैं। जब मौसम प्रतिकूल होता है तो इन मौसमी व्यवसायों में लगे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है।

(ख) संरचनात्मक बेरोजगारी–

विकास के साथ– साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती रहती है। किसी एक क्षेत्र में माँग कम होती है तो किसी दूसरे क्षेत्र में माँग बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के साथ–साथ माँग का स्वरूप भी बदलता रहता है। इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है।

(ग) तकनीकी बेरोजगारी–

उत्पादन की तकनीक में सुधार तथा नवीन मशीनों के उपयोग के कारण जो बेरोजगारी होती है वह तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है।

(घ) घर्षणात्मक बेरोजगारी–

इसे भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है। दो रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह कार्य बदलने, हड़ताल, तालाबन्दी आदि के कारण उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है।

(ङ) चक्रीय बेरोजगारी–

अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के उतार चढ़ावों (तेजी–मंदी की स्थिति) को व्यापार चक्र कहा जाता है। व्यापार चक्रों मे जब मंदी की स्थिति होती है तो समग्र माँग का स्तर बहुत कम हो जाता है। इससे उत्पादन एवं रोजगार में भी गिरावट हो जाती है। समग्र माँग में कमी या व्यापार चक्रों के कारण चक्रीय बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

(च) छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी–

कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है लेकिन कुल उत्पादन में उसका योगदान शून्य या नगण्य होता है। यदि आधिक्य या अतिरिक्त श्रम को उस कार्य से हटा भी लिया जाये तो कुल उत्पादन की मात्रा में कमी नहीं होती है। इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। यह बेरोजगारी अविकसित देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं में अधिक पायी जाती है।

कृषि प्रधान विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण यहां संरचनात्मक तथा छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक पायी जाती है। विकसित देशों में सामान्यतया चक्रीय तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है।

16.3.2 बेरोजगारी के कारण

बेरोजगारी की समस्या अनेक कारणों का संयुक्त परिणाम है। इसके प्रमुख कारण निम्नांकित हैं–

(क) रोजगारपरक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव–

भारत में साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही शिक्षित बेरोजगारी की नयी समस्या भी दृष्टिगोचर हुई है। भारतीय शिक्षा में रोजगारपरकता का अभाव है। यहां शिक्षा की व्यवहारिक उपादेयता बहुत कम है। यहां शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद छात्र रोजगार प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। इसी प्रकार भारत में कौशल प्रदान करने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों का अभाव भी है। प्रशिक्षण व्यक्ति को मानवीय पूंजी बनाता हैं जिससे उसके लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है।

(ख) बढ़ती जनसंख्या तथा श्रम शक्ति–

सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने हेतु अनेक योजनाऐं चलायी जा रहीं हैं लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि के साथ बढ़ती श्रम शक्ति को पूरी तरह खपाने में असफल रही है। भारत में श्रम शक्ति

लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए रोजगार के अवसरों के तेजी से सृजन की आवश्यकता है।

(ग) अनुपयुक्त तकनीक–

भारतीय कृषि तथा उद्योगों में आधुनिक तकनीक को तेजी से अपनाया जा रहा है। यह तकनीक पूँजी गहन तथा श्रम बचतकारी है। भारत जैसे देशों के लिए यह तकनीक उपयोगी नहीं है। भारत में ऐसी तकनीक अपनाये जाने की आवश्यकता है जो यहाँ की विशाल श्रम शक्ति को भी उपयोग में ले सके। अत्याधुनिक तकनीक भी भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है।

(घ) कृषि का पिछड़ापन–

कृषि का पिछड़ापन तथा धीमा विकास भी भारत में बेरोजगारी का बड़ा कारण है। आज भी लगभग 50 प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि तथा सम्बद्व क्षेत्रों मे रोजगार प्राप्त करती है। कृषि क्षेत्र का धीमा विकास इस विशाल जनसंख्या के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में असफल रहा।

(ङ) रोजगार विहीन आर्थिक विकास–

सामान्यतः विकास के साथ रोजगार में भी वृद्धि होती है। भारत ने पिछले 35 वर्षों में तेज गति से विकास किया है, लेकिन इस विकास में सेवा क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत अधिक रहा। सेवा क्षेत्र की रोजगार गहनता कृषि एवं उद्योगों की तुलना में कम होती है अतः तेज आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार के अवसरों मे पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है।

(च) राजनैतिक इच्छाशक्ति एव व्यवस्थित नियोजन का अभाव–

भारत में विकास के साथ–साथ संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप आधिक्य श्रम को व्यवस्थित नियोजन के द्वारा अन्य क्षेत्रों में खपाये जाने की आवश्यकता थी। यद्यपि बेरोजगारी निवारण हेतु सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये गये लेकिन इनमें सामंजस्य का अभाव था। इन कार्यक्रमों में रिसाव बहुत ज्यादा थे अतः इनके समस्त लाभ लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुँच पाये।

16.3.3 बेरोजगारी निवारण के उपाय

बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्यायें इतनी गहनता से जुड़ी हैं कि इनके निवारण हेतु अपनाये जाने वाले उपाय पृथक नहीं हैं। सरकार द्वारा पिछले 40 वर्षों से अनेक मजदूरी रोजगार एवं स्वरोजगार कार्यक्रम चलाकर इनके सहअस्तितव को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी में पर्याप्त कमी लायी गयी है। समानान्तर चल रहे अनेक स्वरोजगार कार्यक्रमों ने शिक्षित एवं कुशल लोगों की बेरोजगारी को कम किया है। अर्थशास्त्रियों का मत है कि बेरोजगारी की दर को शून्य किया जाना सम्भव नहीं है। अर्थव्यवस्था में अल्पमात्रा में संरचनात्मक तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी का अस्तित्व अवश्य ही बना रहता है। बेरोजगारी के कारण एक राष्ट्र अपने अधिकतम सम्भव उत्पादन के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता तथा उत्पादन का एक हिस्सा वो हमेशा के लिए खो देता है जिसे वह सभी को रोजगार प्रदान करके उत्पादित कर सकता था। सरकार द्वारा निम्न उपाय अपनाकर बेरोजगारी में पर्याप्त कमी की जा सकती है।

(क) सरकार द्वारा चलाये जा रहे मजदूरी एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों में उचित समन्वय हो एवं इनमें न्यूनतम रिसाव हो।

(ख) शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाये तथा युवाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

(ग) विकास के साथ–साथ कृषि से मुक्त होने वाले आधिक्य श्रम को खपाने के लिए उद्योगों की वृद्धि दर को तेज किया जाये।

सम्भवतः सरकार द्वारा अपनाया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ''मेक इन इण्डिया'' तथा निवेश प्रोत्साहन उपाय उद्योगों की वृद्धि दर को तेज गति प्रदान करेंगे। तीव्र औद्योगिक विकास के द्वारा बेरोजगारी में भारी कमी की जा सकती है।

(घ) कुशल नियोजन की आवश्यकता–

भारत में प्रतिवर्ष लाखों नये युवा श्रम शक्ति में सम्मिलित होते हैं। यह भारत के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी। उचित नीति बनाकर इन युवाओं के लिए रोजगार सृजन की आवश्यकता है। रोजगार सम्बन्धी नीति इस प्रकार बनायी जानी चाहिए कि इसमें वर्तमान बेरोजगारों के साथ साथ श्रम शक्ति में नव प्रवेश करने वालों को भी ध्यान में रखा जाये।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. मुद्रास्फीति का तात्पर्य सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि से है।
2. मुद्रास्फीति की दर को ज्ञात करने हेतु भारत में थोक मूल्य सूचकांक एवं अनेक प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाये जाते हैं।
3. कीमत तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत सम्बन्ध पाया जाता है।
4. मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु मौद्रिक तथा राजकोषीय उपाय अपनाये जा सकते हैं।
5. भारत में गरीबी के अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में लगाये गये।

6. सुरेश तेंदुलकर के अनुसार वर्ष 2011–12 में भारत में 21.92 प्रतिशत लोग गरीब थे।
7. निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है।
8. बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कार्यकारी आयु वर्ग में शामिल कार्य के योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर रोजगार प्राप्त करने में असफल हो जाता है।
9. भारत में छिपी हुई बेरोजगारी तथा संरचनात्मक बेरोजगारी अधिक पायी जाती है।
10. गरीबी तथा बेरोजगारी के अनुमान लगाने हेतु समंक संकलन का कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ कौनसी हैं ?
2. मुद्रास्फीति की गणना हेतु कौनसे सूचकांक उपयोग में लाये जाते हैं ?
3. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय किसके द्वारा लागू किये जाते हैं ?
4. भारत में गरीबी के सबसे नये अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं ?
5. निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
6. स्वतंत्रता के पश्चात् गरीबी का अध्ययन करने वाले विद्वानों का नाम लिखिए।
7. भारत में गरीबी को मापने का प्रथम प्रयास किसने तथा कब किया ?
8. श्रम शक्ति को परिभाषित कीजिए।
9. छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहा जाता है ?
10. कृषि क्षेत्र में कौनसी बेरोजगारी अधिक पायी जाती है ?
11. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पायी जाती है ?
12. भारत में विश्वसनीय समंकों का संकलन करने वाली संस्था कौनसी है ?

लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. मुद्रास्फीति किसे कहते हैं?
2. स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को समझाइये।
3. मुद्रास्फीति नियंत्रण के राजकोषीय उपायों को समझाइये।
4. मुद्रास्फीति नियंत्रण के मौद्रिक उपाय क्या होते हैं? स्पष्ट कीजिए।
5. निरपेक्ष तथा सापेक्ष गरीबी के मध्य अन्तर बताइये।
6. विभिन्न राष्ट्रों में गरीबी रेखायें अलग–अलग क्यों होती है?
7. भारत में गरीबी के आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए।
8. सुरेश तेंदुलकर द्वारा प्रस्तुत गरीबी के अनुमानों की विवेचना कीजिए।
9. वर्ष 2011–12 के लिए श्रम शक्ति, कार्य शक्ति तथा बेरोजगारी दर के अनुमान क्या हैं?
10. बेरोजगारी से एक व्यक्ति को क्या–क्या हानियाँ होती हैं ?
11. घर्षणात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं ?

निबन्धात्मक प्रश्न–

1. भारत में मुद्रास्फीति के कारणों की विस्तृत विवेचना कीजिए।
2. मुद्रास्फीति से उत्पन्न होने वाली हानियों पर विस्तृत लेख लिखिए।
3. विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा गरीबी के अनुमान लगाने हेतु किये गये प्रयासों की व्याख्या कीजिए।
4. गरीबी निवारण हेतु अपनाये जा सकने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए।
5. बेरोजगारी कम करने हेतु क्या उपाय अपनाये गये हैं तथा अन्य कौनसे उपाय अपनाये जा सकते हैं?